18.10 hrs.

STATEMENT re : CALLING OFF OF STRIKE BY PORT AND DOCK WORKERS

THE MINISTER of SPIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY) : As the hon. Members are aware, the port and dock workers in the major ports resorted to strike in all the ten major ports from the mid-night of 15/16th March, 1984 over their demands for wage revision to be effective from 1-1-1984 for a period of four years. Negotiations with representatives of the four major federations were however continued. I am happy to inform the Hon. Members that, after protracted discussing, a broad understanding for the settlement of the demands was arrived at in the night of 10-4-1984. As a result of the understanding reached, the aforesaid four federation called off the strike in all the ten Major Ports with immediate effect and normal work is being resumed today. The formal settlement is being drafted jointly and is expected to be signed shortly.

2. The main benefits, which are envisaged in the settlement are uniform increase of Rs. 91/- in pay to all employees on rolls as on 31-12-1983 and 1-1-1984, revision of pay scales by merger of D.A. of Rs. 59 in pay, fitment at next higher stage in revised pay scale, benefit of 2 additional increments in the revised scale, grant of H.R.A. in a phased manner during the period of 4 years of settlement at rates ranging from 10% to 30% depending on the classification of the cities, 50% increase in washing allowance and revision of existing piece-rates/incentive rates and special pays and special allowance by 14%. The gross financial implications of the Settlement are expected to be about Rs. 44.7 crores per annum against the federations' last minimum demand indicated at about Rs. 57 crores and Government's offer of about Rs. 40 crores.

3. I take this opportunity of thanking all other departments of the Central Government and the State Governments and local authorities concerned as well as the unions' volunteers for rendering assistance to Port Authorities in carrying out the essential services and in keeping the supply of vital commodities. I sincerely hope that the settlement will bring lasting peace in the major Ports and that the port and dock workers will cooperate with port managements in all respects for improving the efficiency and productivity in major ports.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : You must thank the Naval authorities for that.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : You must also thank the workers. I only want that the Government is honest to implement when once a decision is arrived.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : You must also appreciate the liberal policy of the Government.

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY) : You may not say but the leaders of the Federation have acknowledged that openly.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am happy that we have had a discussion here in the House and it has been settled very well. I also said in the end at that time that it should not be treated as a prestige issue and both sides must settle this issue. It has been done now. I am quite happy about it. I also thank the Minister.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It could have been done much earlier.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY ; I do note want to go into the merits.

AN HON. MEMBER : Shri Satyasadan Chakraborty does not represent the workers.

SHRI SATYASADHAN CHAKRA BORTY : I do.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He represents the teacher-workers.

Shri R. P. Yadav.

---

18 14 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1984-85.

Ministry of Education and Culture—*Contd.*

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, इस मुल्क को आजाद हुए करीब 36 वर्ष हो गये, लेकिन आज तक शिक्षा की कोई नीति देश में नहीं बन पाई है और यह सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, वह इसी से आप जान सकते हैं कि शिक्षा जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, उसकी इन्चार्ज स्टेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ ज्यादा सुविधा होती है और वे कुछ मामलों में स्वयं फैसले ले सकते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर नहीं ले सकते हैं। इस बात से भी आप देख सकते है कि सरकार शिक्षा को कितना महत्व देती है, आज 6 बजे के बाद भी शिक्षा पर बहस कर रहे हैं, हमारे चाहने या न चाहने के बाद भी आप के आदेश के मुताबिक यह बहस जारी है—इससे जाहिर होता है कि आप शिक्षा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी का मुख्य रूप से प्रचार हुआ, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए उन्हें अंग्रेजी जानने वाले क्लर्कों और अफसरों की जरूरत थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब यह सरकार आई तो बारबार यहां पर कहा गया कि हम शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लायेंगे, ताकि देश का लाभ हो सके, लेकिन आपको यह जान कर हैरत होगी कि आज तक शिक्षा के क्षेत्र में एक्स-पेरिमेन्ट्स ही हो रही हैं। आज तक उसका फाइनल शेष इस मुल्क के सामने आया ही नहीं। आपने शुरू में कहा था कि बुनियादी शिक्षा देंगे, फिर आपने उसे हटा दिया। फिर आपने अंग्रेजी को कहा कि कम्पलसरी होगी लेकिन बाद में कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। फिर बाद में आपने एसेसमेंट चलाया और उसको भी खत्म कर दिया है और आज यह 10 + 2 चला रहे हैं लेकिन वह भी देश में सब जगह नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता था कि अगर आप देश में शिक्षा देना चाहते हैं और वास्तव में शिक्षा ही माध्यम होगा देश को आगे ले जाने का और हमारे मुल्क का भविष्य क्या होगा, वह भी शिक्षा पर निर्भर करता है लेकिन आप शिक्षण संस्थाओं में जाकर देखिये कि क्या हो रहा है। शिक्षा की एक नीति तो अवश्य ही होनी चाहिए कि अगर देश व्यापी शिक्षा की नीति नहीं होगी, तो यह देश आगे नहीं जा पाएगा। आप अगर शिक्षण संस्थाओंमें जाएं, तो वहां जाकर आपको मायूसी होगी यह देख कर कि वास्तव में इस मुल्क के बनाने वाले लोगों ने और मुल्क को आजादी दिलाने वाले लोगों ने शिक्षा के बारे में यह सोचा था कि शिक्षा का इस तरह से प्रचार और प्रसार होगा कि गांव के लोगों को भी वही सुविधाएं दी जा सकेंगी जोकि शहरों के लोगों को दी जाती हैं, पर आप कहीं वह चीज नहीं पाएंगे। मैं तो यह चार्ज करना चाहता हूं कि आज सरकार शिक्षा के माध्यम से मुल्क में अलग-अलग क्लास